बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों का परिणाम घोषित

उत्तर प्रदेश ने बीआरएपी 2022 में किया "टॉप अचीवर" का दर्जा प्राप्त

उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करते हुए बीआरएपी 2022 सुधारों का 100% कार्यान्वयन किया प्राप्त

लखनऊ, 5 सितंबर 2024:

उत्तर प्रदेश बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022 में **"टॉप अचीवर" राज्य** बनकर उभरा है। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज हुए उद्योग समागम में यह घोषणा भारत सरकार के **माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल** ने की।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022 में "टॉप अचीवर" का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश ने बीआरएपी 2022 में दो व्यवसाय केंद्रित तथा एक नागरिक केंद्रित क्षेत्र में 'टॉप अचीवर' की उपाधि प्राप्त की। यह मान्यता औद्योगिक विकास में बाधाओं को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित करती है। **माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ** के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

कार्यभार संभालने के उपरांत राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, अनुपालन भार को कम करने और बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इन सुधारों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, जिससे राज्य में व्यवसायों का संचालन सुगम हो गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी-**इन्वेस्ट यूपी**, उत्तर प्रदेश में **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी** है व मुख्य कार्यपालक अधिकारी - इन्वेस्ट यूपी इसके नोडल अधिकारी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022 के अंतर्गत निर्धारित सभी सुधारों को पूर्ण रूप से लागू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। दिल्ली में आयोजित 'उद्योग समागम' का उद्देश्य भारतीय राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बेहतर करना है। अनुकूल कारोबारी वातावरण को प्रोत्साहित करने तथा नियामक ढांचे में सुधार करने की उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता ने राज्य को निवेशकों के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

बीआरएपी 2022 ने व्यापार विनियमन एवं नागरिक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कुल **352 सुधार** संस्तुत किए थे। उत्तर प्रदेश ने इनमें से 100% सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसमें कारोबारी वातावरण में सुधार लाने हेतु केंद्रित **261 कार्य बिंदु** और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बेहतर करने पर केंद्रित **91 कार्य बिंदु** शामिल थे। राज्य के प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी नियामक ढांचा निर्मित हुआ है, जिससे व्यवसायों और नागरिकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं।

सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक **भूमि प्रबंधन और हस्तांतरण** था, जहां उत्तर प्रदेश ने भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया और साथ ही ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रणाली की शुरुआत की। इससे भूमि लेनदेन प्रक्रिया की अवधि और प्रयास में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली, जिसके फलस्वरूप व्यवसायों के लिए भूमि अधिग्रहण करना सुगम हो गया है।

राज्य सरकार ने विभिन्न कानूनों को सरल बनाया, ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण की शुरुआत की तथा विभिन्न विभागों, जैसे- श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और कई अन्य संबंधित स्वीकृतियों के लिए **सिंगल-विंडो सिस्टम - निवेश मित्र** के माध्यम से कार्यान्वयन किया है। इन उपायों से व्यवसायों के लिए नियमों का अनुपालन सुगम हुआ है।

निर्माण परमिट के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली लागू की है और सिंगल विंडो अप्रूवल के लिए विभिन्न विभागों को एकीकृत किया है। इससे निर्माण परमिट प्राप्ति प्रक्रिया की अवधि में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे राज्य में व्यापार करने की सुगमता में सुधार हुआ है। राज्य ने आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और ट्रैकिंग आरंभ करके पर्यावरण स्वीकृति को सुव्यवस्थित करने में भी प्रगति की है, जिससे पारदर्शिता में सुधार हुआ है और विलंब कम हुआ है।

इन विशिष्ट सुधारों के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश ने एक **व्यापक डिजिटल परिवर्तन** को अपनाया है, जो ऑनलाइन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है और सरकारी कार्यालयों में भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को कम करता है। सिंगल-विंडो सिस्टम की शुरूआत ने विभिन्न व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। राज्य ने व्यवसायों एवं नागरिकों से इनपुट एकत्रित करने के लिए फीडबैक तंत्र भी लागू किया, जिससे प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार और समस्याओं के त्वरित समाधान की अनुमति मिली।

इन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनसे कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है। बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय ने व्यवसाय-संबंधित अनुमोदनों और सेवाओं के अधिक सामंजस्यपूर्ण संचालन में भी योगदान दिया है। बीआरएपी 2022 के तहत इन व्यापक सुधारों ने सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश में अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन, निवेश को आकर्षित किया और आर्थिक विकास को गति दी है। इन सुधारों को शत-प्रतिशत लागू करने की राज्य की प्रतिबद्धता भारत में व्यापार एवं निवेश का एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित होने के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है।